तिब्बत देश

भारत के लोग तिब्बती संघर्ष के साथ

इस बार तिब्बतियों द्वारा लोसर (तिब्बती नववर्ष) के अवसर पर कहीं भी विशेष समारोह आयोजित नहीं किए गए। खुशी के अवसर पर भी वे आत्मदाह कर चुके तिब्बती बलिदानियों की याद में पूजा–पाठ तथा प्रार्थना सभाएं कर रहे थे। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. लोबसांग सांगे ने अपील की थी कि वे तिब्बतियों की शहादत का सम्मान करते हुए लोसर के उत्सव नहीं मनायें। उनकी अपील का पूरा असर हुआ, क्योंकि तिब्बती लोग पिछले कुछ महीनों से जारी आत्मदाह की घटनाओं से बहुत ही विचलित एवं बेचैन हैं। तिब्बत की चीनी चंगुल से आजादी तथा भारत में रह रहे परमपावन चौदहवें दलाई लामा जी की तिब्बत में ससम्मान वापसी की मांग करते हुए अनेक तिब्बती स्वयं को आग के हवाले कर चुके हैं। इसीलिए लोसर जैसे खुशी के अवसर पर भी तिब्बती एवं तिब्बत समर्थक स्वाभाविक रूप से शोक संतप्त रहे।

ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार परमपावन तेरहवें दलाईलामा ने 1913 में तिब्बत की आजादी की घोषणा की थी। ज्ञातव्य है कि पहले भी साम्राज्यवादी चीन ने शांतिप्रिय तिब्बत पर अवैध कब्जा कर लिया था। उस समय आजादी की सफल लड़ाई लड़ी गई। तिब्बत आजाद हो गया। पूरे सौ साल बाद 2013 में तिब्बत की आजादी के उसी अवसर को तिब्बत एवं तिब्बत समर्थक उत्साहपूर्ण आयोजनों के जरिए याद कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आत्मदाह का सिलसिला उस दिन भी जारी रहा। उस दिन आत्मदाह की सौवीं घटना घटी। कुछ माह में ही सौ लोगों ने आत्मदाह कर लिए।

शरीर में थोड़ी सी चोट लग जाने पर हम परेशान हो जाते हैं। किसी अंग के थोड़ा जलने से ही हमें दर्द होता है। लेकिन तिब्बती स्वतंत्रता सेनानी चीन सरकार के अत्याचार से तंग आकर स्वयं को पूरी तरह आग के हवाले कर रहे हैं। ये विचलित करने वाले आत्मबलिदान के उदाहरण हैं। तिब्बती चाहते हैं कि विश्व समुदाय चीन पर दबाव बनाये जिससे तिब्बत में चीन सरकार द्वारा जारी क्रूरतापूर्ण दमन बंद हो। तिब्बत की दर्दनाक परिस्थिति के प्रति विश्व समुदाय का ध्यान खींचने तथा सक्रिय समर्थन हासिल करने के लिए ही अनेक तिब्बती आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठा रहे हैं।

तिब्बत की परिस्थिति की गंभीरता 30 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक आयोजित तिब्बत के लिए एकजुटता अभियान के दौरान ज्यादा प्रभावी ढंग से महसूस की गई। दिल्ली के इस आयोजन में तिब्बतियों के साथ ही हजारों तिब्बत समर्थक भारतीयों की भागीदारी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता चीन की उपनिवेशवादी नीतियों की समाप्ति तक अपने आंदोलन को जारी रखने का प्रण कर चुकी है। सभी राजनीतिक–सामाजिक वर्गों के भारतीय इसमें शामिल हुए। अनेक भारतीय राजनेताओं तथा अन्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों ने मांग की कि भारत सरकार तिब्बतियों के पक्ष में चीन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए जारी आंदोलन का नेतृत्व करे। उनका मत है कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा। तिब्बत ऐतिहासिक रूप से भारत एवं चीन का मध्यस्थ राज्य (बफर स्टेट) रहा है। तिब्बत की सुरक्षा से ही भारत भी सुरक्षित रहेगा।

भारतीय मीडिया में तिब्बत संबंधी व्यापक चर्चा इस बात का सुखद संकेत है कि भारतीय जनता भारत की सुरक्षा एवं शांति के लिए तिब्बत के महत्व को समझने लगी है। लोग राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों से खुलेआम पूछ रहे हैं कि वे तिब्बत में जारी मानवाधिकार हनन पर चुप क्यों हैं? आगामी आम चुनाव के समय तिब्बत का मुद्दा भी छाया रहेगा, इसकी पूरी संभावना दीख रही है। भारतीय समाज में लगभग हर वर्ग के लोग संगठित होकर इस विषय पर विशेष अभियान चला रहे हैं। वे तिब्बतियों द्वारा जारी प्रयासों को भी ज्यादा मजबूत बनाने में लगे हैं। डॉ. लोबसांग सांगे ने तिब्बतियों से आग्रह किया था कि वे आत्मदाह कर चुके अनेक तिब्बतियों की याद में 20 फरवरी को विश्व स्तर पर शोक सभाएं करें। अच्छी बात है कि तिब्बत समर्थक भारतीयों ने भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की।

अभी माहौल है उपयुक्त कदम उठाने का। संयुक्त राष्ट्र संघ समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चाहिये कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार तथा विश्व शांति की सुरक्षा के लिए तिब्बत–संकट का समाधान करें। उनके संगठित प्रयासों के आगे चीन की साम्राज्यवादी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इस मामले में विशेष भूमिका भारत सरकार को निभानी है। चीन की भारत विरोधी गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है। चीन हर क्षेत्र में भारत को घेरने, नीचा दिखाने और बर्बाद करने की नीतियों पर चल रहा है। भारत सरकार को चाहिये कि वह अपने हितों की सुरक्षा के लिए तिब्बती संघर्ष का साथ दे। विश्व के अनेक तिब्बत समर्थक देश एवं संगठन भारत सरकार की सक्रिय भूमिका का इंतजार कर रहे हैं।

भारत सरकार की ताकत है भारतीय जनता। भारतीय जनता की तिब्बत संबंधी मांगों की उपेक्षा करना सरकार के लिए ठीक नहीं है। चीन के साथ बनावटी दोस्ती के नाम पर भारतीय हितों के साथ खिलवाड़ देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए भारत सरकार को तिब्बत–समस्या के हल हेतु चीन सरकार से सार्थक वार्ता अवश्य करनी चाहिए।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)
मो.–9829806065 | 8764060406
E-mail & facebook: shyamnathji@gmail.com

दिल्ली के एकजुटता अभियान में तिब्बत के दुःखद हालात को दर्शाया गया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, फरवरी, 2013)

धर्मशाला के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने 30 जनवरी को नई दिल्ली में चार दिवसीय 'तिब्बती जन एकजुटता अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत के दिन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी रहे। इस समारोह में तिब्बत सरकार के सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे और तिब्बती संसद के स्पीकर पेनपा सेरिंग के अलावा कांग्रेस सांसद सुश्री प्रिया दत्त एवं डॉ. ई.एम. सुदर्शन नतचिप्पन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद श्री हसन खान ने भी शिरकत की।

इस कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए जिसमें भारत, नेपाल, भूटान से आए करीब 4,500 तिब्बती और दिल्ली एवं इसके आसपास के इलाकों तथा लद्दाख से आए करीब 1,000 भारतीय समर्थक शामिल थे।

अगले तीन दिनों में तिब्बती और उनके भारतीय समर्थकों ने एक विशाल रैली, एक सेमिनार, दिन भर तक चलने वाली प्रार्थना सभा, एक विशाल जनसभा और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें तिब्बत में जारी दुःखद हालात को प्रदर्शित किया गया, जहां वर्ष 2009 से अब तक करीब 99 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। 31 जनवरी को आयोजित सेमिनार में सिक्योंग लोबसांग सांगे ने हिस्सा लिया। उनके साथ इस सेमिनार में भारत के पूर्व विदेश सचिव श्री ललित मान सिंह, भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव श्री जयदेव रानाडे और धर्मशाला स्थित कीर्ति मठ के प्रमुख कीर्ति रिनपोछे भी शामिल हुए।

इंडिया इंटरनेशन सेंटर में आयोजित इस सेमिनार का विषय थाः "तिब्बतः मौजूदा स्थिति और चीन एवं भारत पर इसके निहितार्थ।" इसके पहले सिक्योंग लोबसांग सांगे, स्पीकर पेनपा सेरिंग और कालोन डोलमा ग्यारी ने राजघाट से जंतर–मंतर तक आयोजित एक शांति मार्च का नेतृत्व किया। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर आयोजित एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुई। इसमें बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जैन, हिंदू, सिख, बहाई और यहूदी धर्म गुरुओं ने प्रार्थनाएं कीं। निर्वासित तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट पर 31 जनवरी को दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्रार्थना सभा में 7,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। शांति मार्च अंत में एक जनसभा में बदल गई जिसे विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।

एक फरवरी को जंतर–मंतर पर दिनभर तक चलने वाली प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसका नेतृत्व तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा के 102वें ताज धारक गादेन त्रि रिनपोछे ने किया। इस सभा में भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने भी शिरकत की। तिब्बत डॉट नेट के अनुसार इस प्रार्थना सभा में 6,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।

अभियान के चौथे दिन 2 फरवरी को 6,000 तिब्बतियों के साथ 1,500 से ज्यादा भारतीय समर्थकों ने जंतर मंतर पर आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस सभा को 30 से ज्यादा भारतीय नेताओं ने संबोधित किया जिसमें कई सांसद, पार्टियों के शीर्ष नेता और युवा नेता शामिल थे। इनमें भारत के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व रेल मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री राम विलास पासवान, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं राज्य सभा में विपक्ष के उप नेता श्री रविशंकर प्रसाद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चंदन मित्रा शामिल थे। सभा को संबोधित करने वाले अन्य नेताओं में भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री बलबीर पुंज, भाजपा सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा सांसद सुश्री बिमला कश्यप, समाजवादी पार्टी के सांसद श्री आलोक तिवारी, राष्ट्रीय लोकदल के सांसद और महासचिव श्री जयंत चौधरी, बिहार के पूर्व राज्य मंत्री और झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय महासचिव श्री एस.एम. कमर आलम और पूर्व राजदूत श्री रंजीत गुप्ता शामिल थे।

तिब्बतियों को शिकायत करने का मौका दें: अमेरिका ने चीन से कहा

(फायूल, 8 फरवरी, 2013)

चीन ने 70 तिब्बतियों को एक साथ जेल में डालकर तिब्बत में आत्मदाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। इसे देखते हुए अमेरिका ने चीन से अनुरोध किया है कि वह तिब्बतियों को आज़ादी से अपनी शिकायतें व्यक्त करने का मौका दे।

पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने चीनी नेतृत्व से अपील की कि वह तिब्बत की समस्या का कोई स्थायी हल निकालने के लिए परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बिना शर्त सार्थक बातचीत करे। न्यूलैंड ने कहा, "हमें तिब्बती इलाकों में कुलमिलाकर बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति को लेकर गहरी चिंता है, न केवल दुःखद आत्मदाह की घटनाओं को लेकर बल्कि इससे जुड़े लोगों पर जिस तरह से आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जा रही, उसे लेकर भी। तिब्बती जनता को काफी शिकायतें हैं जिनका चीन सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं कर रही।"

गौरतलब है कि पूर्वी तिब्बत की चीनी अदालतों ने कई तिब्बतियों को लंबे समय तक के लिए कारावास की सजा सुनाई हैं और एक तिब्बती को दो साल के लिए विलंबित मौत की सजा दी गई है। इनका "अपराध" यह बताया गया है कि आत्मदाह के साथ विरोध प्रदर्शन करने के मामलों से उनका संबंध था। वर्ष 2009 से ही करीब 99 तिब्बतियों ने चीन शासन का विरोध करते हुए और स्वाधीनता तथा परमपावन दलाई लामा को निर्वासन से वापस बुलाने की मांग करते हुए खुद को आग लगा लिया है।

एक सवाल के जवाब में न्यूलैंड ने कहा कि अमेरिका के नए विदेश मंत्री जॉन केरी ने अपने चीनी समकक्ष के साथ फोन पर शुरुआती परिचयात्मक बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने चीन में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले उठाए हैं। न्यूलैंड ने कहा, "चीन के साथ वरिष्ठ स्तर के किसी भी संवाद में हमने हमेशा ही मानवाधिकारों और खासकर तिब्बत के बारे में अपनी चिंता जताई है।"

उन्होंने कहा, "हमने चीन सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के सार्थक वार्ता करे ताकि तिब्बत की जनता की शिकायतें दूर हो सकें और वहां तनाव खत्म हो सके। हम लगातार चीन सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वह तिब्बतियों को स्वतंत्र, सार्वजनिक और शांतिपूर्ण तरीके से तथा बिना किसी बदले की कार्रवाई के भय के अपनी शिकायतों के इजहार का मौका दे।

आत्मदाह के मामले में तिब्बतियों को भारी सजा की चौतरफा आलोचना

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 3 फरवरी, 2013)

धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने 1 फरवरी को चीन सरकार की इस बात के लिए निंदा की कि उसने 31 जनवरी को आठ तिब्बतियों को विलंबित मौत सहित काफी कठोर सजा दी है। कुछ अन्य तिब्बतियों को कथित रूप से आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में दो अलग–अलग मुकदमों के द्वारा कठोर सजा सुनाई गई है। चीन सरकार के इस कदम की चौतरफा आलोचना हो रही है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने इसे बेहद कठोर सजा बताते हुए कहा कि यह निर्णय बिना समुचित कानूनी प्रक्रिया और वकील के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिए ही सुना दिया गया है। न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने भी कहा है कि तिब्बतियों को काफी कठोर सजा दी गई है और उनका अपराध बस इतना था कि उन्होंने आत्मदाह के बारे में चर्चा की थी। पहले मुकदमे में एक तिब्बती को विलंबित मौत की सजा और एक अन्य तिब्बती को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। इसकी चर्चा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने 1 फरवरी को चीन से अनुरोध किया कि वह तिब्बतियों को स्वतंत्र, सार्वजनिक, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी बदले की कार्रवाई के भय के अपनी शिकायतों को प्रकट करने का मौका दे। उन्होंने 40 वर्षीय भिक्षु लोबसांग कोंछोक और उनके 31 वर्षीय भतीजे लोबसांग सेरिंग के मामले का हवाला दिया जिनके कथित रूप से जानबूझकर नरहत्या में शामिल होने के आरोप में सिचुआन प्रांत के नाबा प्रशासनिक अदालत ने सजा सुनाई है।

एचआरडब्ल्यू ने भी पहले मुकदमे का हवाला देते हुए चीन के न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे तत्काल इन दो तिब्बतियों को रिहा करें जिन्हें इस तरह की कानूनी प्रक्रिया में दोषी साबित किया गया है जो सिर्फ उनके पांच माह हिरासत में रहने के दौरान किए गए कबूलनामे पर आधारित है। संगठन की चीन की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने कहा, "यह मुकदमे बिल्कुल विश्वसनीय नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि "कुछ लोगों द्वारा छोड़े गए बयानों से यह साफ होता है कि वे सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध जता रहे थे।" उन्होंने 1 फरवरी को जारी बयान में कहा, "चीन सरकार यह सोचती है कि जो भी आत्मदाह की बात भी करेगा उसको सजा देकर वह आत्मदाह पर रोक लगा लेगी। लेकिन इस तरह के 'उकसाने' वाले मामले को आगे बढ़ाकर चीन सरकार आत्महत्या के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दुःखद हालात को और बढ़ा रही है।"

मानवाधिकार फिल्म समारोह में तीन तिब्बती फिल्मों का प्रदर्शन किया गया

(फायूल, 6 फरवरी, 2013)

वैश्विक मानवाधिकार की स्थिति पर नार्वे के शहर ओस्लो में आयोजित एक फिल्म समारोह में तिब्बत पर खास ध्यान दिया गया और इसमें तीन प्रमुख तिब्बती डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। "ह्यूमन राइट्स ह्यूमन रांग्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल" का आयोजन 5 से 10 फरवरी तक किया गया और इसमें "मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति और नार्वे एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में मानवाधिकारों पर फिल्म निर्माण के बारे में असाधारण फिल्मों का प्रदर्शन, संवाद और चर्चा का आयोजन किया गया।" इस साल इस फिल्म समारोह के पांचवें संस्करण का विषय था, "देशनिकाला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन और मुनाफा/आर्थिक अन्याय।"

इस समारोह में तीन पुरस्कृत तिब्बती डॉक्यूमेंट्री "लिविंग फियर बिहाइंड", "द सन बिहाइंड द क्लाउड" और "तिब्बत इन सांग" का प्रदर्शन किया गया। जेल में बंद तिब्बती फिल्म निर्माता धोनढुप वांगछेन की चर्चित डॉक्युमेंट्री फिल्म "लिविंग फियर बिहाइंड" में बीजिंग ओलंपिक 2008 की तैयारी के दौर में तिब्बतियों के जीवन को दर्शागया गया है। तिब्बत नाइट में सबसे पहले इसका प्रदर्शन किया गया। वर्ष 2012 के इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवॉर्ड के विजेता वांगछेन को चीनी प्रशासन द्वारा 26 मार्च, 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था और "विध्वंस" के आरोप में 28 दिसंबर, 2009 को एक गोपनीय मुकदमे में उन्हें छह साल जेल की सजा सुनाई गई।

इसके बाद रितु सरीन और तेनजिन सोनम की अवॉर्ड हासिल फिल्म 'द सन बिहाइंड द क्लाउड्स' का प्रदर्शन किया गया और अंत में तिब्बती संगीतकार गवांग छोफेल की फिल्म 'तिब्बत इन सांग' का प्रदर्शन किया गया। तिब्बती शरणार्थी छोफेल अध्ययन के लिए वापस तिब्बत गए थे और उन्होंने वहां परंपरागत तिब्बती संगीत को रिकॉर्ड किया था। लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर 18 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हालांकि, बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए चीन सरकार ने छह साल में ही उन्हें रिहा कर दिया। उनकी फिल्म के बारे में कहा गया है कि यह "सांस्कृतिक उत्पीड़न और प्रतिरोध की मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसमें तिब्बत में लोकगीतों के फिल्मांकन के लिए गवांग की अपनी सजा शामिल है और इसका अंत आज के तिब्बत पर एक रोशनी के साथ होता है, एक ऐसा देश जो अब भी चीन की बर्बरता से त्रस्त है और फिर भी अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जूझने को तैयार है।"

समारोह में 7 फरवरी को एक समूह चर्चा हुई जिसका विषय थाः तिब्बतीः मानवाधिकारों के लाभार्थी या सांस्कृतिक नरसंहार के शिकार?" इस चर्चा में शामिल लोगों में तिब्बती संसद के सदस्य छुंगदाक कोरेन, गवांग छोफेल और ओस्टीन एल्मे प्रमुख थे। कोरेन ने 8 फरवरी को एक चर्चा में तिब्बत में चल रहे आत्मदाह के लहर और चीनी प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी चर्चा की। इस चर्चा का विषय थाः "कई देशों में बिना किसी समर्थन के विरोध प्रदर्शन, इन देशों में चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय क्या कर सकता है।"

'ह्यूमन राइट्स ह्यूमन रांग्स फिल्म समारोह' का आयोजन ओस्लो के ह्यूमन राइट्स हाउस और ओस्लो डोकुमेंटरकिनो (ओस्लो डॉक्युमेंट्री सिनेमा) द्वारा किया गया। यह फिल्म समारोह पहली बार दिसंबर 2008 में मानवाधिकारों की घोषणा की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था और वर्ष 2010 से इस समारोह को वार्षिक आयोजन कर दिया गया।

चीन ने आस्ट्रेलियाई अधिकारियों के तिब्बत दौरे पर रोक लगा रखी है

(सिडनी मार्निंग हेराल्ड, 14 फरवरी, 2013)

करीब एक साल तक कोशिश करने के बाद भी चीन में आस्ट्रेलिया की एक शीर्ष राजनयिक तिब्बत दौरे के लिए चीन की इजाजत हासिल करने में नाकाम रही हैं। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री बॉब कार ने मार्च 2012 में घोषणा की कि राजदूत फ्रांकेस एडमसन तिब्बत का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत करना चाहती हैं और यह जानना चाहती हैं कि आखिर क्यों लगातार इतनी बड़ी संख्या में स्वाधीनता समर्थक तिब्बती खुद को आग लगाकर जान दे रहे हैं। सीनेटर कार ने कैनबरा में गुरुवार को सीनेट की एक सुनवाई में कहा, "दुर्भाग्य से मेरे पास आपको देने के लिए कोई उत्साहजनक समाचार नहीं है। मुझे दुख है कि इस बारे में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।" सुश्री एडमसन ने कई बार चीन सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक उन्हें इजाजत नहीं मिली है।

विदेश मंत्रालय और व्यापार सचिव पीटर वर्गीज ने कहा कि आस्ट्रेलिया को पता चला है कि पिछले दो साल में तिब्बत में आत्मदाह की कम से कम 98 घटनाएं हुई हैं। हमने तिब्बत के हालात के बारे में चीनी अधिकारियों को लगातार अपनी चिंता से अवगत कराया है।"

सीनेटर कार का कहना है कि आस्ट्रेलिया चीन के साथ अपने राजनयिक रिश्ते और मजबूत करना चाहता है, लेकिन फिलहाल इस योजना पर विराम लगा हुआ है क्योंकि मार्च के बाद चीन में नए नेतृत्व के आने का इंतजार है। उन्होंने अक्टूबर में खुलासा किया था कि कई शीर्ष आस्ट्रेलियाई अधिकारी चीन के दौरे पर गए थे ताकि कैनबेरा और बीजिंग के बीच नियमित औपचारिक संपर्क बढ़ाया

जा सके। यह व्यवस्था उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके तहत आस्ट्रेलिया ने अमेरिका जैसे कई देशों से अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, लेकिन उसके इस प्रस्ताव का अभी चीन से सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

नई व्यवस्था में आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के साथ वार्षिक मुलाकात और दोनों देशों के विदेश तथा आर्थिक मंत्रियों के बीच अलग–अलग बैठकें आयोजित करने को शामिल किया जा सकता है।

तिब्बतियों की उम्मीद भारत पर टिकी

(पीटीआई, 7 फरवरी)

तिब्बती सांसदों ने अपनी संस्कृति की रक्षा में भारत की मदद की तारीफ की है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि तिब्बत मसले का हल भारत के हाथ में है। तिब्बती संसद के सदस्य और निर्वासित तिब्बती संसद की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सेरिंग दावा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम भारत सरकार और यहां की जनता द्वारा समय से मिलने वाली मदद और देखभाल के लिए भारी शुक्रगुजार हैं। इसकी वजह से ही हम अपनी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रख पाए हैं जो कि तिब्बत में रहकर संभव नहीं हो पाता।" दावा ने कहा, "अब तिब्बत मसले के समाधान के लिए सबकी उम्मीद भारत सरकार और यहां की जनता पर है।"

उन्होंने कहा, "वर्ष 2009 से अब तक 99 तिब्बतियों ने दलाई लामा की वापसी का समर्थन करते हुए और तिब्बत में स्वाधीनता की बहाली की मांग करते हुए आत्मदाह जैसा चरम कदम उठाया है। इनमें से 80 को अपनी जान गंवानी पड़ी है और बाकी बचे लोग चीन की जेलों में बंद हैं।"

उन्होंने कहा कि दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कभी भी ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित नहीं किया है, लेकिन तिब्बत के बाहर रहकर इन गतिविधियों पर नियंत्रण भी नहीं लगाया जा सकता। दावा ने कहा कि तिब्बत के लिए एकजुटता अभियान में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए तिब्बती सांसदों के तीन समूह का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन समूह के सांसदों ने जितने भी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है उनमें से लगभग सभी ने हांगकांग या मकाओ की तर्ज पर तिब्बत को स्वायत्तता देने का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा, "तिब्बत सरकार वार्ता में यकीन करती है और वह तिब्बत पर किसी भी समय, कहीं भी धर्मशाला–बीजिंग वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन 2009 से चीन सरकार से कोई आधिकारिक संपर्क नहीं है। हालांकि, अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क बना हुआ है।"

तिब्बत से आने वाले नए शरणार्थियों ने सुनाई दमन की दास्तान

(वायस ऑफ अमेरिका, 20 फरवरी)

तिब्बत से हाल में निर्वासित होकर धर्मशाला आने वाले तिब्बतियों ने यह सच्चाई बयान की है कि किस तरह से 2008 के बाद से ही तिब्बत में चीनी दमन बढ़ गया है। धर्मशाला स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र ने यह जानकारी दी है। हाल में आए एक तिब्बती लोबसांग सामफेल नाबा के आमदो इलाके के रहने वाले हैं, जहां 2009 में आत्मदाह की घटनाएं शुरू हुई थीं और जहां आत्मदाह की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं।

सामफेल ने निर्वासित तिब्बती संगठन टीसीएचआरडी से कहा, "गत 16 जून, 2008 को दोपहर करीब 12 बजे 20 पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी हमारे मठ आए उन्होंने एक मठ की इमारत पर चीनी झंडा लगाने का प्रयास किया।" सामफेल ने बताया कि भिक्षुओं ने मठ की इमारत पर चीनी झंडा लगाने के प्रयास का विरोध किया और वे इसे रोकने में सफल भी रहे।

लगभग उसी समय काउंटी के कस्बे में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें स्थानीय मिडल स्कूल के छात्रों, कीर्ति मठ के भिक्षुओं और आम तिब्बतियों सहित करीब 800 लोगों ने हिस्सा लिया। सामफेल ने कहा कि जब स्थानीय गोमांग मठ के भिक्षुओं को इस प्रदर्शन की जानकारी मिली तो वहां से भी करीब 500 तिब्बती इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। सामफेल ने कहा कि चीनी सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना शुरू किया और कई प्रदर्शनकारियों को उकसाया गया कि वे स्थानीय सुरक्षा बल कार्यालय की इमारत और एक अदालत में आग लगाएं।

सामफेल ने बताया, "मैंने देखा कि चीनी सुरक्षा बलों ने 21 वर्ष की एक तिब्बती महिला ल्हुनढुप सो को गोली मार दी जो कि तिब्बती रेस्टोरेंट और दुकानों के दरवाजे पर खाता (पवित्र स्कार्फ) लटका रही थी। इस तरह का पवित्र खाता इसलिए लटकाया जाता है ताकि दुकान या प्रतिष्ठान की बरकत हो सके। इसके बाद मैंने देखा कि विरोध प्रदर्शन स्थल पर ही दो तिब्बती युवाओं को गोली मार दी गई। शाम को आसपास के गांवों के कई वरिष्ठ भिक्षु और बुजुर्ग तिब्बतियों ने प्रदर्शन रोकने की अपील की क्योंकि उन्हें आशंका थी कि सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई करेंगे और बहुत से लोगों की जानें जाएंगी। इसके बाद आखिरकार विरोध प्रदर्शनकारी अपने घर चले गए। तिब्बत से हाल में आने वाले एक और शरणार्थी जिग्मे ग्यालत्सेन ने भी तिब्बत में जारी बर्बर दमन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "तिब्बत में तिब्बतियो को किसी तरह की आज़ादी नहीं है।"

दो तिब्बती किशोरों की आत्मदाह के बाद मौत, संख्या 104 तक पहुंची

(फायूल डॉट कॉम, 20 फरवरी)

पूर्वी तिब्बत के जोएगे स्थित क्यांगत्सा इलाके में दो तिब्बती किशोरों ने गत 19 फरवरी को तिब्बत पर चीनी कब्जे और दमनकारी नीतियों के खिलाफ खुद को आग लगा लिया। 17 वर्षीय रिनछेन और 18 वर्षीय सोनम धार्गे ने बहुत ज्यादा जल जाने की वजह से दम तोड़ दिया।

कीर्ति मठ के धर्मशाला स्थित निर्वासन के केंद्र के अनुसार इन दोनों किशोरों ने स्थानीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे यह अग्निमय विरोध प्रदर्शन किया।

कीर्ति मठ ने एक बयान में कहा, "अभी यह नहीं पता चल पाया है कि इस विरोध प्रदर्शन के समय वे क्या नारे लगा रहे थे। दोनों किशोरों के परिवारों ने शवों को अपने पास ले लिया था और उन्हें उम्मीद है कि वे चीनी प्रशासन के दखल के बिना इनका अंतिम संस्कार कर पाएंगे।"

रिनछेन के मां–बाप का नाम धोनढुप सेरिंग और स्वर्गीय आदोन है, जबकि सोनम धार्ग्ये के मां–बाप सेरिंग धोनढुप और ताखो हैं। इस खबर की पुष्टि करते हुए धर्मशाला स्थित केंद्रीय मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र ने कहा कि रिनछेन और सोनम धार्ग्ये, दोनों ने क्यांगत्सा के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की थी।

टीसीएचआरडी ने कहा, "प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद रिनछेन ने कुछ वर्षों तक वेनचुआन के एक और स्कूल में पढ़ाई की और वह क्विंघई चले गए जहां उन्होंने कुछ काम किया। आत्मदाह के समय रिनछेन लोसार (नए साल) की छुट्टियां बिताने अपने परिवार के पास क्यांगत्सा आए हुए थे।

इस तरह अब तक चीनी शासन के तहत रहने वाले कम से कम 104 तिब्बतियों ने स्वाधीनता और परमपावन दलाई लामा को निर्वासन से वापस लाने की मांग करते हुए खुद को आग लगा लिया है। इस साल की शुरुआत से ही अब तक तिब्बत में इस तरह के अग्निमय विरोध प्रदर्शन की आठ घटनाएं हो चुकी हैं। गत 13 फरवरी को नेपाल के शहर काठमांडू में भी एक तिब्बती भिक्षु ड्रुपछेन सेरिंग ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आत्मदाह कर लिया।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच ने इस माह की शुरुआत में कहा था कि तिब्बत में आत्मदाह चीन सरकार की "तिब्बती इलाकों में लंबे समय से जारी दमनकारी नीतियों की वजह से हो रही हैं जहां तिब्बतियों के अधिकारों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं।

नेपाल में आत्मदाह करने वाले तिब्बती का निधन, काठमांडू में सख्त निगरानी

(फायूल, 14 फरवरी, 2013)

नेपाल की राजधानी काठमांडू मैं बुधवार, 13 फरवरी को आत्मदाह करने वाले तिब्बती भिक्षु का निधन हो गया है। इस भिक्षु की पहचान अभी तक साफ नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय टीचिंग हॉस्पिटल में बुधवार रात 10.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि यह भिक्षु काफी 'गंभीर' हालत में अस्पताल आए थे और वे 96 फीसदी जल गए थे। नेपाल मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें सुबह 8.45 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संगठन के अध्यक्ष अस्पताल के अंदर गए थे और तिब्बती भिक्षु का उपचार कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की थी। डॉक्टरों ने सांस लेने में आसानी के लिए घायल भिक्षु के गले में एक चीरा लगाया था और उन्हें दर्द की कई दवाइयां दी थीं। मानवाधिकार संगठन के एक सदस्य शम्भू लामा ने फायूल को बताया, "डॉक्टरों ने बताया कि घायल तिब्बती पहले तिब्बती में कुछ बोल रहे थे, लेकिन पांच मिनट के बाद यह भी बंद हो गया।" हालांकि मानवाधिकार संगठन भी इस भिक्षु के नाम की पहचान नहीं कर पाया, लेकिन अस्पताल में मौजूद एक तिब्बती ने उनका नाम लोबसांग बताया है। हालांकि, नेपाली पुलिस उनका नाम ध ोनढुप लोत्से बता रही है। उनकी उम्र 30 वर्ष से कम बताई जा रही है।

गौरतलब है कि इस तिब्बती भिक्षु ने तिब्बत में चीनी कब्जे के विरोध में काठमांडू के बौद्धनाथ स्थित पवित्र बौद्ध

स्तूप के पास खुद को आग लगा लिया था।

एक पुलिस अधिकारी केशव अधिकारी ने एपी को बताया कि यह व्यक्ति एक कैफे में घुसा, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। एपी को एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भिक्षु आग की लपटों में घिर जाने और जमीन पर गिरने से पहले चीन के खिलाफ नारे लगाते हुए कुछ दूर तक दौड़े थे। इस विरोध प्रदर्शन की घटना के बाद समूचे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। आत्मदाह की यह घटना 13 फरवरी को हुई है, जिस दिन परमपावन महान 13वें दलाई लामा द्वारा "तिब्बती स्वाधीनता की घोषणा" की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी।

बुधवार की शाम को काठमांडू के जवालाखेल स्थित सामढुपलिंग बस्ती के तिब्बती निवासियों ने आत्मदाह करने वाले भिक्षु के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए गोपनीय तरीके से जुटकर एक मोमबत्ती जुलूस निकाला और प्रार्थना सभा आयोजित की।

इस सभा के एक आयोजक बताया कि स्थानीय प्रशासन के भारी प्रतिबंधों के बावजूद, "नवजात बच्चों से लेकर समुदाय के बुजुर्ग लोगों तक" सभी तिब्बती इस जुलूस में शामिल हुए।

हाल के वर्षों में नेपाल ने अपने यहां रहने वाले करीब 20,000 तिब्बती समुदाय के लोगों की सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति पर लगातार दमन बढ़ाया है। वित्तीय मदद के लिए नेपाल की लगातार चीन पर बढ़ती निर्भरता की वजह से तिब्बती शरणार्थियों की आज़ादी पर अंकुश लगाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में तिब्बत से भागकर नेपाल आने की कोशिश कर रहे कई तिब्बतियों को पकड़कर वापस चीन भेज दिया गया है।

निर्वासित तिब्बती सरकार के सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे इन दिनों अमेरिका में हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था, "तिब्बत के भीतर आत्मदाह मुख्य वजह तिब्बत पर चीनी कब्जा और तिब्बतियों का दमन ही है।" सिक्योंग सांगे ने कहा, "तिब्बत के दुःखद हालात का हल निकालना चीन के हाथों में ही है और मेरा प्रशासन उनसे बात करने और समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

वर्ष 2009 से अब तक चीन के शासन के तहत रहने वाले करीब 100 तिब्बतियों ने स्वाधीनता और परपावन दलाई लामा को निर्वासन से वापस लाने की मांग करते हुए खुद को आग लगा लिया है।

निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों में से आत्मदाह करने वाले काठमांडू के भिक्षु तीसरे व्यक्ति हैं। इसके पहले 1998 में थुबटेन गोधुप और मार्च 2012 में जामफेल येशी ने आत्मदाह कर लिया था।

वरिष्ठ तिब्बती भिक्षु नई राजनीतिक शिक्षा को मजबूर किए जा रहे हैं

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 1 फरवरी, 2013)

चीन ने तिब्बती धार्मिक समुदाय पर नए सिरे से दमनात्मक कार्रवाई शुरू की है। चीनी अधिकारी 14 प्रमुख भिक्षुओं को राजनीतिक पुनर्शिक्षा देने के लिए उत्तरी तिब्बत स्थित एक मठ में लेकर गए हैं। ये भिक्षु तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के दिग्गज धार्मिक केंद्रों से हैं। रेडियो फ्री एशिया की खबर के अनुसार इन सभी 14 भिक्षुओं को एक 'विशेष बैठक' के बहाने 14 जनवरी को बुलाया गया, लेकिन उनके मठ से बाहर निकलते ही उन्हें पकड़ लिया गया और तब से ये गायब हैं।

खबरों के मुताबिक ल्हासा के भीतर और उसके आसपास स्थित सेरा, ड्रेपंग, गाडेन मठ और जोखांग मंदिर के इन वरिष्ठ भिक्षुओं को पूर्वी तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के नागछू स्थित पेनकार मठ ले जाया है।

ड्रेपंग मठ से इस शिक्षण के लिए ले जाए जाने वाले भिक्षुओं में मठ अध्यक्ष जामफेल ल्हाक्सम, धार्मिक कीर्तन प्रमुख गवांग और गवांग डोनडेन, गवांग पालसांग एवं गवांग सामतेन जैसे कई शिक्षक शामिल हैं।

सेरा मठ से अनुशासन प्रमुख मिगमार, धार्मिक कीर्तन प्रमुख सामतेन और नागवांग, लोडरो एवं टाशी ग्यालत्सेन जैसे शिक्षकों को ले जाया गया है। इसी तरह गांदेन मठ से वरिष्ठ भिक्षुओं कालदेन और लोबसांग गोड्डुब को पकड़कर ले जाया गया है। जोखांग मंदिर से सेतेन दोरजे, ल्हुनड्रुप यारफेल और गवांग लोफेल को पकड़ा गया है। तिब्बत में नए सिरे से धार्मिक दमन होने की औपचारिक तौर पर पुष्टि 29 जनवरी को ही हो गई थी, जब टीएआर जन कांग्रेस की समाप्ति पर बड़बोले और सख्त रवैए वाले लोबसांग ग्यालत्सेन को टीएआर का नया गवर्नर बनाने की घोषणा की गई।

तिब्बतियों के आत्मदाह में कथित तौर पर सहयोग के लिए आठ लोगों को सजा

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 1 फरवरी, 2013)

चीन सरकार ने 31 जनवरी को कहा है कि उसने कुछ तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह करने में कथित तौर पर भूमिका के लिए आठ तिब्बतियों को तीन साल जेल से लेकर विलंबित मौत तक की सजा सुनाई है। यह सजा सिचुआन प्रांत की एक प्रशासनिक अदालत और गांसू प्रांत की एक काउंटी अदालत ने सुनाई है। इस बात के संकेत मिले हैं कि असल में जिन तिब्बतियों को सजा सुनाई गई है उनका अपराध बस इतना ही था कि उन्होंने आत्मदाह के बारे में जानकारी, तस्वीरें बाहर भेजी थीं और उन्होंने इस घटना के वक्त पुलिस दमन का विरोध किया था।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आं

1. नई दिल्ली के तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में निर्वासित तिब्बती प्रशासन द्वारा आयोजित तिब्बत एकजुटता अ
आडवाणी और कांग्रेस की तरफ से उसकी आधिकारिक प्रतिनिधि सांसद प्रिया दत्त भी 30 जनवरी, 2013 को
2. सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे और स्पीकर पेनपा सेरिंग सहित निर्वासित तिब्बत प्रशासन के शीर्ष नेता तिब्बत
जनवरी, 2013 को आयोजित एक विशाल रैली का नेतृत्व करते हुए।
3. नई दिल्ली में चार दिवसीय तिब्बती जन एकजुटता अभियान के दौरान 1 फरवरी 2013 को तिब्बत में जारी
4. तिब्बती जनता के एकजुटता अभियान के दौरान नई दिल्ली में 30 जनवरी, 2013 को निर्वासित तिब्बती सरक
से बातचीत करते हुए।
5. तिब्बत में चीन के लगातार जारी कब्जे के विरोध में प्रदर्शन करते हुए धर्मशाला में सैकड़ों तिब्बती और उनके
नीतियों के खिलाफ नामल्हा सेरिंग के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घटना के साथ ही तिब्बत में 18 फरवरी,
6. नई दिल्ली में तिब्बती जन एकजुटता अभियान के दौरान आयोजित एक मार्च में शामिल निर्वासित तिब्बती अ
7. पूर्वी तिब्बत के कुमबुम में तिब्बती नव वर्ष मनाने वाले स्थानीय तिब्बतियों को घेरे हुए चीनी पुलिस। फोटोः
8. मानवाधिकारों और लोकतंत्र पर पांचवें जेनेवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कालोन डिक्की छोक्यांग। इस
किया गया था।
9. काठमांडू में 13 फरवरी, 2013 को एक भिक्षु द्वारा आत्मदाह के प्रयास के बाद मोमबत्ती जुलूस निकालते नि
10. तिब्बती नव वर्ष (लोसार) के 15वें दिन धर्मशाला के सुग–ला–खांग मंदिर के परिसर में जातक कहानियों (महात
परमपावन दलाई लामा।

(8)

(9)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

की आंख से

एकजुटता अभियान में जुटे 5,000 से ज्यादा तिब्बती और भारतीय समर्थक। भारत के पूर्व उप–प्रधानमंत्री लालकष्ण
री, 2013 को शुरू इस चार दिवसीय आयोजन में पहुंचे थे।
नेता तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भारत की राजधानी नई दिल्ली में 31

त में जारी आत्मदाह की लहर के बारे में एक नाटक का मंचन करते हुए टीसीवी स्कूल, गोपालपुर के तिब्बती विद्यार्थी।
तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे (बाएं) भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता लालकष्ण आडवाणी

ी और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। तिब्बत के लाबरांग क्षेत्र में स्थित सांगचू में चीन सरकार की दमनकारी
18 फरवरी, 2013 तक आत्मदाह करने वालों की संख्या बढ़कर 102 तक पहुंच गई।
त तिब्बती और बौद्ध भिक्षु हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए। फोटोः डेक्कन क्रॉनिकल/एजेंसीज
स। फोटोः फायूल
क्यांग। इस सम्मेलन का आयोजन जेनेवा स्थित संगठन यूएनवाच और 20 एनजीओ के एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन द्वारा

निकालते निर्वासित तिब्बती। फोटोः गेट्टी इमेज
हानियों (महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी) पर आयोजित एक उपदेश के दौरान मुस्कराते हुए तिब्बती आध्यात्मिक गुरू

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी

(5)

(7)

(6)

की दिशा में)

पहले मामले में चीन सरकार ने बताया है कि उसने सिचुआन प्रांत के अबा प्रशासनिक क्षेत्र में एक विद्वान भिक्षु को मौत की सजा सुनाई है, लेकिन इस सजा पर अमल दो साल के लिए विलंबित रखा गया है। इसी तरह इन विद्वान के भतीजे, जो कि एक निरक्षर पशुपालक हैं, उन्हें भी कथित तौर पर जानबूझकर नरहत्या में शामिल होने के आरोप में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इन दोनों तिब्बतियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वर्ष 2012 में आठ तिब्बतियों को आत्मदाह के लिए उकसाया और ऐसे तीन लोगों को उकसाने में उन्हें सफलता मिल गई जिन्होंने खुद को जलाकर जान दे दी।

माएरकांग स्थित प्रशासनिक अदालत के आदेश के हवाले से चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने 31 जनवरी को खबर दी है कि गेशे डिग्री (डॉक्टरेट के समकक्ष) धारी 40 वर्षीय लोरांग कोंछोक को दो साल तक विलंबित मौत की सजा दी गई है और उनसे सभी तरह के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए हैं। उनके भतीजे 31 वर्षीय लोरांग सेरिंग को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है और उसके भी राजनीतिक अधिकार तीन साल के लिए छीन लिए गए हैं। अदालत के आदेश में कहा गया है कि इन दोनों लोगों के उकसाने पर आत्मदाह करने वाले लोरांग सेड्डुप, सेनाम और जोकबा की मौत हो गई, जबकि बाकी पांच लोगों ने आत्मदाह करने का विचार त्याग दिया या पुलिस ने हस्तक्षेप कर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। गौरतलब है कि विलंबित मौत की सजा को अक्सर दो साल के बाद आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी होता है कि सजा पाया हुआ व्यक्ति इस दौरान अच्छा व्यवहार करे।

छह और लोगों को 12 साल तक सजाः दूसरी तरफ, गांसू प्रांत स्थित गन्नान की एक काउंटी अदालत ने गत 31 जनवरी को छह तिब्बतियों को तीन से लेकर 12 साल तक के कारावास की सजा सुनाई। इन सभी लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर अक्टूबर 2012 में एक स्थानीय ग्रामीण को आत्मदाह के लिए उकसाया था। शिनहुआ ने दो अलग खबरों में इसकी जानकारी दी है।

खबर के मुताबिक सांगछू काउंटी की अदालत ने पदमा तामड्डु, केलसांग ग्यामुक्त्सो, पदमा को और ल्हामो तामड्डु को "जानबूझकर नरहत्या" करने का दोषी माना है क्योंकि इन लोगों ने कथित तौर पर आत्मदाह करने वाले दोर्जे रिनछेन को "बचाने" में लगी पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की। इन सभी लोगों को क्रमशः 12, 11, 8 और 7 साल तक जेल की सजा सुनाई गई है। खबर के मुताबिक दो अन्य तिब्बतियों दो गेक्याप और यांग मोंजे को क्रमशः चार और तीन साल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने "अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश" की।

नवंबर 2012 में हुए आत्मदाह के लिए एक ही प्रशासनिक क्षेत्र के 70 लोग गिरफ्तार

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 8 फरवरी)

चीन ने 7 फरवरी को कहा है कि उसने क्विंघई प्रांत के हुआंगनान प्रशासनिक क्षेत्र में एक "अपराध के शक" में 70 तिब्बतियों को हिरासत में लिया और आखिरकार इनमें से 12 लोगों को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों को नवंबर 2012 में हुए लगातार कई आत्मदाह के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ से क्विंघई प्रांतीय जनसुरक्षा विभाग के उप प्रमुख ल्यू बेनक्वियान ने कहा कि पुलिस उन लोगों को गंभीरता से सजा दी जाएगी जो निर्दोष लोगों को आत्मदाह के लिए उकसाते हैं।

खबर के मुताबिक लिउ ने कहा कि इसके पीछे दिमाग 'दलाई लामा गुट' का है और यह गुट ही आत्मदाह को बढ़ावा दे रहा है। ल्यू आत्मदाहों की जांच कर रही विशेष पुलिस टीम के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जैसे उनकी तस्वीर विदेशों में भेजने से आत्मदाहों को बढ़ावा मिल रहा है। इसी तरह आत्मदाह में मरने वाले या घायल होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने से भी आत्मदाह को बढ़ावा मिल रहा है।

आत्मदाह के पीछे क्या इरादा हो सकता है, इसके बारे में ल्यु ने कहा, "ऐसे कई पीड़ित कुंठित थे, जीवन से निराश हो चुके थे और वे आत्मदाह करके अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते थे।" ल्यु ने यह भी कहा कि "कुछ अतिराष्ट्रवाद की प्रबल भावनाओं वाले लोग इन आत्मदाह करने वालों के साथ सहानुभूति थी और उन्होंने भी इनके रास्ते पर चलने का निर्णय लिया।"

ल्यु ने दावा किया कि कुल मिलाकर आत्मदाह के ये मामले दलाई गुट के अलगावावाद से प्रभावित हैं क्योंकि विदेशों में रहने वाले तिब्बती अलगाववादी उन्हें "नायक" की तरह पेश करते हैं। उन्होंने कहा, "पड़ोसी सिचुआन और गांसू प्रांतों में होने आत्मदाह से हुंगागनान में और आत्मदाह को बढ़ावा मिला रहा है।"

ह्यूमन राइट्स वाच ने चीन पर प्रतिबंध लगाया

(फायूल, 4 फरवरी)

एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने चीन के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को देखते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतरराष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वाच ने यह प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि दुनिया के इस सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश ने वर्ष 2012 में "राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों" पर मामूली प्रगति की है। न्यूयॉर्क स्थित इस संगठन ने पिछले हफ्ते जारी अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2013 में कहा है कि चीन का मानवाधिकार रिकॉर्ड पूरे साल के दौरान "खराब बना रहा"। ह्यूमन राइट्स वाच के सोफी रिचर्ड्सन ने कहा, "चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लिउ जियाओबो को आज भी जेल में बंद करके रखा है और दुर्भाग्य से यह इस बात का दर्पण है कि चीन में आज़ादी की क्या स्थिति है।"

संगठन की 665 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है, "जब चीन के अपने नागरिक चुनौती देते हैं वहां की सरकार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि वह व्यवस्थित सुधारों की जगह दमन का सहारा लेती है या रणनीतिक तरीके से पीछे हट जाती है।" ऐसे साल में जब तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ 100 से ज्यादा आत्मदाह हो चुके हैं, एचआरडब्ल्यू का कहना है, "तिब्बत के पठार में 2008 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद जिस तरह से व्यापक सख्त कार्रवाई की गई उससे तिब्बती इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "सरकार को अभी यह संकेत देना है कि वह व्यापक स्वायत्तता की तिब्बती जनता की आकांक्षाओं पर ध्यान देगी, यहां तक कि जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिए बने देश के स्वायत्तता कानून के सीमित दायरे में ही सही।"

इस बात पर गौर करते हुए कि "प्रताड़ना और जबरन अपराध कबूलवाना आपराधिक न्याय प्रणाली में आम बात हो चुकी है," एचआरडब्ल्यू ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने आत्मदाह के जवाब में "और ज्यादा सख्त कदम उठाए हैं, जैसे आत्मदाह करने वालों के रिश्तेदारों और उनके पड़ोसियों को सामूहिक सजा दी जा रही है।" अंतरराष्ट्रीय संगठन का कहना है कि जिन तिब्बतियों पर यह संदेह है कि वे सरकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उनको लगातार 'अलगाववादी' बताकर निशाना साधा जा रहा है।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "चीनी सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर मौजूदगी है और अधिकारियों ने खासकर पत्रकारों और विदेशी पर्यटकों के लिए तिब्बती इलाके तक पहुंचने या वहां की यात्रा करने पर सख्त प्रतिबंध जारी रखे हैं।"

एचआरडब्ल्यू ने आरोप लगाया है कि चीन सरकार ने तिब्बत में "एक नया समाजवादी देहात" बनाने के लिए ऐसे "बड़े विकास कार्यक्रमों को लागू कर रही है जिसमें 80 फीसदी ग्रामीण जनता को नए मकान में जाना या नई जगह पर बसना अनिवार्य कर दिया गया है।"

एचआरडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "बिना किसी प्रभावी विकल्प और प्रभावित लोगों को बिना किसी सही परामर्श के (चीन सरकार के दावे के विपरीत) विस्थापन नीतियों को लागू किया जा रहा है। इसी तरह, मुआवजे की नीति भी पूरी तरह से अपारदर्शी और अपर्याप्त है। चरवाहों को उनकी परंपरागत जीविका से वंचित किया जा रहा है जिसकी वजह से उनका जीवन स्तर और घटिया होता जा रहा है, तथा वे सरकार की सब्सिडी पर निर्भर होते जा रहे हैं।"

नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों की हालत पर चिंता जताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि, "चीन के बढ़ते दबाव की वजह से नेपाल सरकार ने लगातार तिब्बतियों को भारत तक सुरक्षित रास्ता दिए जाने से इनकार किया है और उसने तिब्बतियों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने या जुटने पर भी रोक लगा रखी है।"

संगठन ने कहा कि चीन में हाल में शी जिनपिंग के नेतृत्व में जिस सात सदस्यीय नई समिति का गठन किया गया है उसे देखकर भी यह साफ होता है कि नए शीर्ष नेताओं के चयन की चीनी जनता के राजनीतिक आकांक्षा के बुनियादी अधिकारों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है।

संगठन ने कहा कि "नए राजनीतिक नेतृत्व को अभी यह संकेत देना है कि वह कानून के शासन, जवाबदेही और सरकार में खुलापन की लगातार बढ़ती मांग पर गौर करने के इच्छुक हैं।" रिपोर्ट में कहा गया है, "आंदोलनकारियों, सरकार के आलोचकों और साधारण नागरिकों को कई तरह के दमन का सामना करना पड़ रहा है। इनमें पुलिस की निगरानी एवं प्रताड़ना, लोगों को निराधार तरीके से घर में कैद रखना, मनमाने तरीके से जेल में डाल देना और जबर्दस्ती मनोचिकित्सा केंद्रों में भेज देना या मानवाधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले लोगों पर राजनीति प्रेरित आरोप लगाकर जेल में डाल देने जैसे दमनकारी कार्य शामिल हैं।"

रिपोर्ट के अनुसार चीन में अकेले जितने कैदियों को फांसी दी जाती है, उतना पूरी दुनिया में मिलाकर भी नहीं दी जाती। चीन सरकार ने पिछले साल दिसंबर माह में इंटरनेट पर भी सेंसरशिप और बढ़ा दी है। लोगों के असली नाम पता करने और मनचाही सामग्री को ब्लॉक करने के देश के "ग्रेट फायरवाल" के सॉफ्टवेयर से ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा मानवाधिकार संगठन ने एक आरोप यह भी लगाया है कि देश में 90 फीसदी अंग प्रत्यारोपण फांसी वाले कैदियों के अंग से किया जा रहा है।

तिब्बत के अस्तित्व की जंग

कुलदीप नैयर

लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

एक समय था जब तिब्बती विद्रोह में उठ खड़े हुए। उनके बीच मौजूद खम्पाओं ने उनके हाथ में हथियार थमाए, लेकिन चीनियों ने शस्त्रों और संख्या बल द्वारा बेरहमी से उन्हें कुचल डाला। उन पर किए गए अत्याचार असंख्य थे, किंतु तिब्बतियों ने कभी हथियार नहीं डाले। यहां तक कि बड़े पैमाने पर तैनात चीनी सेना खम्पाओं और तिब्बतियों के हाथों आज भी असुरक्षित और परेशान महसूस करती है।

जब भी मैं दलाईलामा को व्यक्तिगत रूप में या फिर किसी चित्र में देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा आदमी है, जो हजारों वर्ष पहले की संस्कृति का संचालन करता है और यह बखूबी जानता है कि उसका एक अनिश्चित भविष्य है। तिब्बत इस संस्कृति का घर है, एक देश जो चीन के अधीन है जो केवल एक संस्कृति को जानता है, साम्यवाद। जो उसके अलावा हर बात को मिटा देना चाहता है। तिब्बती संस्कृति का नया घर धर्मशाला में फैला है, जो भारत में एक पर्वतीय क्षेत्र है।

दलाईलामा कितनी भी कोशिश करें, जिस तिब्बती संस्कृति का बीहड़ में वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह मुरझा रही है क्योंकि तिब्बत से उखड़ा यह पौधा नए वातावरण में फल–फूल नहीं रहा है। तिब्बती और बौद्ध सत्याग्रह के माध्यम से दमन के 50 वर्षों बाद भी बीजिंग की शक्ति का विरोध कर रहे हैं, वही रास्ता अपना कर जो भारत ने ब्रिटिश शासकों को खदेड़ने के लिए अपनाया था, लेकिन चीन अलग है। उसने अलग रह रहे तिब्बतियों के दमन के लिए दहषत का रास्ता अपनाया है और उनमें से कुछेक ने तो अपनी दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आपको जिंदा जला डालने का रास्ता भी अपनाया है। पहले से ही बेचैन अंतरराष्ट्रीय समाज 15 महिलाओं सहित 99 लोगों के आत्म बलिदान पर संत्रस्त महसूस करता है, लेकिन चीन ने केवल अपने दमन को बढ़ा दिया है और सैकड़ों संभावित आत्म बलिदान करने वालों को हिरासत में ले लिया है।

कुछेक को कानूनी न्यायालयों में ले जाया गया है। कैद की सजा सुनाई गई है ताकि व्यवस्था के एक ढोंग द्वारा विश्व को ठगा जाए। दलाईलामा आत्म बलिदान के विरुद्ध हैं। वह भारत में हैं जहां उन्हें सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन चीन के हमेशा उकसाने वाले विरोधों के कारण अबाधित स्वतंत्रता नहीं। यह 1959 की बात है, जब दलाईलामा हजारों तिब्बतियों के साथ चीन के निरंकुश शासन से बच निकले और भारत में शरण ली। स्थानीय लोग तिब्बती निवास को पसंद नहीं करते, लेकिन वे जानते हैं कि धार्मिक आस्था और परंपराओं में बौद्ध हिंदुओं के जैसे ही हैं। इसलिए तिब्बती संस्कृति ने उस उत्तेजना पर विजय पा ली है क्योंकि जिस आत्मत्याग का दलाईलामा प्रचार करते हैं अंततः एक हिंदू भी उसी की आकांक्षा रखता है।

दलाईलामा प्रायः भविष्य की बात करते हैं और यह समझते हैं कि तिब्बतियों को आखिरकार घर लौटना है। एक मध्यमार्ग के तौर पर उन्होंने देश के भीतर ही तिब्बत के लिए एक स्थिति की पेशकश की है, लेकिन बीजिंग ने लंबी बातचीत के बाद हाल ही में इस समीकरण को रद्द कर दिया है। चीन का साम्यवाद एक ऐसे संगठित समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक ऐसी स्वायत्तशासी संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है जो विषय वस्तु के लिहाज से धार्मिक हो। एक समय था जब तिब्बती विद्रोह में उठ खड़े हुए। उनके बीच मौजूद खम्पाओं ने उनके हाथ में हथियार थमाए, लेकिन चीनियों ने शस्त्रों और संख्या बल द्वारा

बेरहमी से उन्हें कुचल डाला। उन पर किए गए अत्याचार असंख्य थे, किंतु तिब्बतियों ने कभी हथियार नहीं डाले। यहां तक कि बड़े पैमाने पर तैनात चीनी सेना खम्पाओं और तिब्बतियों के हाथों आज भी असुरक्षित और परेशान महसूस करती है। बीजिंग, नई दिल्ली को दोष देता है जो बार–बार चीन को यह आश्वस्त करती है कि यह भारत की करनी नहीं है। दलाईलामा और उनके मठवासी अनुयायियों को शरण देने के बाद भारत ने सीमा सील कर दी है। उसने तिब्बत से अपने हाथ धो दिए हैं, जिसे अंग्रेजों ने अगस्त 1947 में भारत छोड़ते समय भारत के संरक्षण में छोड़ दिया था।

चीन के पक्ष को सही मानें तो भारत ने तिब्बत का अधिराज्य बीजिंग को हस्तांतरित कर दिया है। भले ही नई दिल्ली इसका पछतावा करता है या नहीं अधिराज्य का अर्थ आधिपत्य नहीं है। अधिराज्य राजनीतिक नियंत्रण को सौंप देना है, सभी अधिकारों को समाप्त कर देना नहीं जैसा नई दिल्ली ने किया है।

यह अतिस्वामित्व है जो प्रभुसत्ता से कई पायदान नीचे है। फिर भी चीन से आतंकित भारत ने तिब्बतियों की दुर्दशा पर सवाल तक नहीं उठाए हैं। न ही वह तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नियंत्रण के लिए तिब्बत का प्रयोग करने पर चीन से शंका प्रकट करने में स्पष्ट रहा है। तिब्बती पठार और इसका अड़ोस–पड़ोस अधिकांष चीन, भारत तथा बांग्लादेश के लिए ताजे जल का साधन होने के अतिरिक्त चीनी भूभाग का एक चौथाई हिस्सा गठित करता है।

तिब्बत भूमि का वह छोर है जिस पर भारत तथा चीन के तनावर्पूण भू–राजनीतिक संबंध र्निभर हैं। तिब्बत इसलिए भी अनूठा है क्योंकि चीनी प्रभुत्व के विरुद्ध यहां के लोगों का संघर्ष एक वैश्विक करिश्माई व्यक्तित्व दलाईलामा पर केंद्रित है, लेकिन उनके बाद तिब्बत का क्या होगा? असल में नई दिल्ली ने दलाईलामा के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिन्हें भारतीय तटों को छोड़ने से पहले उसे सूचना देनी होती है।

कई बार उन्हें कहा गया है कि जो उन्होंने कहा है उसे उन्हें नहीं कहना चाहिए था। तिब्बत के बारे में चीन का संदर्भ दिया जाना वर्जित है और उन्हें संस्कृति और धर्म के क्षेत्र तक सीमित रहने के लिए कहा गया है। तिब्बती संस्कृति के लिए भविष्य में क्या नियत है या फिर स्वयं तिब्बतियों के लिए? इस सवाल का जवाब भारत द्वारा कभी नहीं दिया गया है, जो यह देखकर आश्वस्त महसूस करता है कि वे धर्मशला और इसके आसपास के स्थानों तक सीमित हैं। फिर भी दलाईलामा ने अपने लोगों के भविष्य के प्रति अपनी व्यथा व्यक्त की है। उनके पास कोई चारा नहीं है और न ही अधिक उम्मीद है। यदि प्रार्थनाओं से सहायता मिल पाती तो उन्होंने उस मार्ग को बताने के लिए उस परमपिता के आगे अनेकों बार साष्टांग दंडवत किया है। विश्व इस अन्याय को देख रहा है, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलता। कहीं ऐसा न हो कि चीन, जो एक महाशक्ति बन चुका है, नाराज हो जाए और हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सांस लेने के लिए छटपटा रही है।

उसे पता है कि वह जीवित रहेगी, किसी विशेष स्थान पर नहीं बल्कि तिब्बतियों के हृदय में जो अब संख्या में कम रह गए हैं।

तिब्बती स्वतंत्रता का आत्मदाह

डा. कुलदीप चंद अग्निहोत्री
लेखक, वरिष्ठ स्तंभकार

तिब्बत के भीतर आजादी का आंदोलन कभी समाप्त नहीं हुआ। कभी प्रत्यक्ष और कभी प्रच्छन्न उसकी तपिश बीजिंग तक पहुंचती ही रही। 2009 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों ने संघर्ष के एक नए तरीके को जन्म दिया, जिसकी मिसाल दुनिया भर में हुए स्वतंत्रता संघर्षो में शायद ही कहीं मिलती हो। वह था, स्वयं को अग्निदेव के हवाले कर स्वतंत्रता की देवी की आराधना करना।

कुछ दिन पहले एक और तिब्बती भिक्षु ने तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को होम दिया। उसने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया। इस प्रकार आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों की संख्या सौ हो गई है।

तिब्बत के भीतर आजादी के लिए लड़ रहे तिब्बतियों ने संघर्ष के इस अध्याय की शुरुआत 2009 में की थी। अब तक स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राणोर्त्सग करने वाले इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या सौ हो गई है। तिब्बत पर कब्जा करने की शुरुआत, चीन पर माओ के कब्जा करने के साथ ही 1949 में शुरू हो गई थी। उस वक्त तिब्बत को आशा थी कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार तिब्बत के साथ खड़ी होगी, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। नेहरू उस समय चीन को अपना स्वाभाविक साथी मानते थे। अलबत्ता भारत की जनता जरूर इस मौके पर तिब्बत के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। उसके बाद 1959 में तो चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा ही कर लिया और दलाई लामा को भाग कर भारत आना पड़ा। तब से तिब्बत के लोग चीन से आजादी पाने के लिए संघर्ष रत हैं।

चीन तिब्बत की संस्कृति, धर्म और भाषा को समाप्त कर उसका अस्तित्व मिटाने के प्रयास में लगा हुआ है। सांस्कृतिक क्रांति के दिनों में चीनी सेना ने वहां के सभी मंदिर मठ ध्वस्त कर दिए थे और ल्हासा के तीनों विष्व प्रसिद्ध विश्वविद्यलयों को धराशायी कर दिया था, लेकिन तिब्बतियों के भीतर के आजादी के जज्बे को चीन की सेना समाप्त नहीं कर पाई। तिब्बत के भीतर आजादी का आंदोलन कभी समाप्त नहीं हुआ। कभी प्रत्यक्ष और कभी प्रच्छन्न उसकी तपस बीजिंग तक पहुंचती ही रही।

2009 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों ने संघर्ष के एक नए तरीके को जन्म दिया, जिसकी मिसाल दुनिया भर में हुए स्वतंत्रता संघर्शों में शायद ही कहीं मिलती हो। वह था, स्वयं को अग्निदेव के हवाले कर स्वतंत्रता की देवी की आराधना करना। इन आराधकों में ज्यादातर युवा पीढ़ी के लोग ही हैं।

पंद्रह वर्ष के एक बालक तक ने इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सबसे बड़ी बात यह कि यह सारा संघर्ष अहिंसात्मक तरीके से हो रहा है। जो व्यक्ति अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए ही तत्पर हो जाता है, वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। भय तब तक ही रहता है, जब तक आदमी अपने प्राणों को बचाने की फिराक में रहता है, लेकिन जिसे अपने ही प्राणों का मोह नहीं वह भला किसी से क्यों डरेगा। मानव बम बनने के पीछे यही मनोविज्ञान काम करता है। लेकिन आत्मदाह करने वाले किसी एक भी तिब्बती स्वतंत्रता सेनानी ने किसी चीनी को नुकसान पहुंचाने या मारने का प्रयत्न नहीं किया, जबकि ऐसा करना उनके लिए बहुत सहज और आसान था। इससे पता चलता है कि तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम कितने अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है।

चीन के इन आरोपों में कोई दम नहीं है कि तिब्बत की आजादी के लिए लड़ने वाले हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं और वे आतंकवादी हैं । दरअसल चीन तो तिब्बतियों को उत्तेजित कर रहा है कि वे हिंसा का प्रयोग करें, क्योंकि चीन जानता है कि केवल मात्र साठ लाख की आबादी वाले तिब्बतियों को शासकीय हिंसा से कुचलना कितना आसान है। तिब्बती स्वतंत्रता सेनानी उचित ही चीन के इस जाल में न फंस कर त्याग और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

यहां एक और महत्त्वर्पूण प्रश्न है कि सारी दुनिया में, कहीं भी तथाकथित मानवाधिकारों के प्रश्न को लेकर आंसू बहाने वाली भारत सरकार तिब्बत में चीन सरकार द्वारा किए जा रहे इस अमानवीय कृत्य पर चुप क्यों है? मध्य पूर्व में पिछले दिनों हुए जनांदोलनों में मानवाधिकारों को लेकर भारत सरकार

की चिंता समझी जा सकती है, लेकिन पड़ोसी देश तिब्बत में जो हो रहा है, उसकी निंदा स्वरूप सरकार के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। कम से कम मानवीय आधार पर ही भारत सरकार इस पर अपनी चिंता तो प्रकट कर ही सकती थी, जबकि तिब्बत के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक व सामाजिक संबंध हैं।

चीन के साथ चल रही द्विपक्षीय वार्ताओं में तिब्बत में हो रहे इस नरमेध का विषय सरकार को जरूर उठाना चाहिए। अफजल गुरु की फांसी को लेकर जंतर–मंतर पर रुदाली का अभिनय करने वालों की विवशता तो समझ में आ सकती है, क्योंकि उनका रोना–धोना दिल से नहीं बल्कि एक रणनीति से संचालित होता है, लेकिन भारत सरकार तो मानवीय आधारों को तरजीह देती है, ऐसी घोषणा बराबर की जाती है।

अपनी इन घोषणाओं के अनुरूप ही भारत सरकार को चीन द्वारा तिब्बतियों की प्रताड़ना के मसले को वैश्विक मंचों पर उठाना चाहिए। जाहिर है कि यदि भारत इस दिशा में कोई पहल करेगा तो शक्ति संतुलन की अमरीकी रणनीति के तहत भी तिब्बत के मसले को जगह मिल सकेगी। वर्षों से आत्मदाह की आग में जल रहे तिब्बत को भारत की कूटनीतिक सहायता की जरूरत है।

यह ऐसा मौका है, जब इस मुद्दे की तपिश दुनिया भर के अनेकों देशों में दलाई लामा के प्रवास के कारण महसूस की जा रही है। इस मौके का लाभ उठाते हुए भारत का चहुंमुखी घेराव का प्रयास कर रहे चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। गुरु गोलवलकर ने कहा था तिब्बत चीन के कब्जे में हमारी कमजोरी से ही गया है, इसका प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। प्रायश्चित करने का इससे उपयुक्त अवसर भला और क्या हो सकता है।

तिब्बती स्वाधीनता की घोषणा का शताब्दी समारोह

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 19 फरवरी)

तेरहवें दलाई लामा द्वारा 13 फरवरी, 1913 को की गई तिब्बत की स्वाधीनता की घोषणा की दुनिया भर में मनाए जा रहे शताब्दी समारोह का समापन छात्रों के एक वैश्विक नेटवर्क के अभियान से हुआ। इस अभियान के तहत तिब्बत की स्वाधीनता हासिल करने के लिए हर साल इस दिन को तिब्बत स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल तिब्बत स्वाधीनता दिवस को तिब्बत के इतिहास के बारे में चीन के दुष्प्रचार को चुनौती देने के लिए भारी साधन के रूप में और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर तिब्बती आत्मनिर्धारण के मामले को मनाया गया। न्यूयॉर्क स्थित स्टुडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत के कार्यकारी निदेशक तेनजिन दोरजी ने कहा, "इस साल से हम तिब्बती स्वाधीनता दिवस को तिब्बती इतिहास के बारे में चीन के दुष्प्रचार को चुनौती देने और वैश्विक मंच पर तिब्बती आत्मनिर्धारण के मामले को मजबूत करने के एक शक्तिशाली साधन के रूप में मनाया।"

संगठन ने कहा कि इस अवसर पर दुनिया के 30 से ज्यादा शहरों में कार्यक्रम किए गए जिनमें से बहुत से कार्यक्रम दूसरे संगठनों के साथ मिलकर किए गए। इस कार्यक्रमों से यह आह्वान किया गया कि तिब्बत को चीनी शासन से पूरी तरह से स्वाधीन किया जाए। तेनजिन दोरजी ने कहा, "कई शहरों में हमने तिब्बती युवा कांग्रेस और अन्य संगठनों से गठजोड़ किया ताकि तिब्बती स्वाधीनता दिवस को दुनिया भर की जनता के दिमाग में बिठाया जा सके।"

स्वाधीनता दिवस के उद्घाटन समारोह के तहत आस्ट्रेलिया, ताइवान, भारत, जापान, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड जैसे दर्जनों देशों के 30 से ज्यादा शहरों में झंडारोहण समारोह, प्रदर्शनियां, जनमत निर्माण कार्यक्रम और चीनी दूतावासों एवं वाणिज्य दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। संगठन ने कहा कि कनाडा, अमेरिका और स्कॉटलैंड के संसद सदस्यों द्वारा इस शताब्दी समारोह का सम्मान करते हुए समर्थन के लिए सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किए गए।

धर्मशाला में तिब्बतियों और उनके समर्थकों ने एक प्रदर्शनी में हिस्सा लिया जिसमें एक स्वाधीन दिवस के रूप में तिब्बत के ऐतिहासिक दर्जे को रेखांकित किया गया और तिब्बत की स्वाधीनता को बचाए रखने के लिए 13वें दलाई लामा और उनके प्रयासों पर एक चर्चा का आयोजन किया गया।

ड्रांगो विरोध प्रदर्शन की घटना के बाद पांच तिब्बतियों को कठोर सजा

(फायूल डॉट कॉम, 19 फरवरी, 2013)

ड्रांगो की एक चीनी अदालत ने पिछले साल की शुरुआत में इलाके में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के लिए पांच तिब्बतियों को 10 से 14 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने बताया कि ड्रांगो की माध्यमिक जन अदालत ने गत 26 जनवरी को ड्रांगो मठ के दो भिक्षुओं और तीन आम तिब्बती नागरिकों को यह सजा दी। इन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने "विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और एक सार्वजनिक बैंक का लूटा था।"

23 जनवरी, 2012 को विरोध प्रदर्शन करने और अन्य को इन प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उकसाने के आरोप में दोनों भिक्षुओं टाशी धारग्याल और नामग्याल धोनढुप को 14 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। इन दोनों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2008 में समूचे तिब्बत में हुई जनक्रांति में हिस्सा लिया था।

एक अन्य तिब्बती नागरिक थ्रिनले को विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने और प्रदर्शनों के दौरान "एक बैंक लूटने" के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दो अन्य अज्ञात तिब्बतियों 11–11 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

ड्रांगो में चीनी नव वर्ष के पहले दिन 23 जनवरी को सैकड़ों तिब्बती सड़कों पर आ गए और उन्होंने तिब्बत को स्वाधीनता देने तथा परमपावन दलाई लामा को निर्वासन से तिब्बत वापस लाने के नारे लगाए। चीनी सुरक्षा बलों ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध तरीके से गोलीबारी शुरू कर दी जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए और तमाम लोग घायल हो गए।

यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब स्थानीय चीनी जन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों ने इस इलाके में आत्मदाह की लहर के बाद जगह–जगह लगे पोस्टरों और पत्रकों को वितरित करने में शामिल होने के संदेह में कुछ तिब्बतियों की मनमाने तरीके से गिरफ्तारी शुरू कर दी।

इन पोस्टरों में चेतावनी दी गई थी कि यदि चीन सरकार ने तिब्बतियों की चिंताओं पर गौर नहीं किया तो और आत्मदाह होंगे। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद चीनी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर इसमें शामिल होने के संदेह में लोगों की तलाशी शुरू की, सैकड़ों तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया और ड्रांगों की एक पहाड़ी के पास छिपे दो भाइयों की हत्या कर दी गई।

तिब्बत से आने वाले नए शरणार्थियों ने सुनाई दमन की दास्तान

(वायस ऑफ अमेरिका, 20 फरवरी)

तिब्बत से हाल में निर्वासित होकर धर्मशाला आने वाले तिब्बतियों ने यह सच्चाई बयान की है कि किस तरह से 2008 के बाद से ही तिब्बत में चीनी दमन बढ़ गया है। धर्मशाला स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र ने यह जानकारी दी है। हाल में आए एक तिब्बती लोबसांग सामफेल नाबा के आमदो इलाके के रहने वाले हैं, जहां 2009 में आत्मदाह की घटनाएं शुरू हुई थीं और जहां आत्मदाह की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं।

सामफेल ने निर्वासित तिब्बती संगठन टीसीएचआरडी से कहा, "गत 16 जून, 2008 को दोपहर करीब 12 बजे 20 पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी हमारे मठ आए उन्होंने एक मठ की इमारत पर चीनी झंडा लगाने का प्रयास किया।" सामफेल ने बताया कि भिक्षुओं ने मठ की इमारत पर चीनी झंडा लगाने के प्रयास का विरोध किया और वे इसे रोकने में सफल भी रहे।

लगभग उसी समय काउंटी के कस्बे में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें स्थानीय मिडल स्कूल के छात्रों, कीर्ति मठ के भिक्षुओं और आम तिब्बतियों सहित करीब 800 लोगों ने हिस्सा लिया। सामफेल ने कहा कि जब स्थानीय गोमांग मठ के भिक्षुओं को इस प्रदर्शन की जानकारी मिली तो वहां से भी करीब 500 तिब्बती इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। सामफेल ने कहा कि चीनी सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना शुरू किया और कई प्रदर्शनकारियों को उकसाया गया कि वे स्थानीय सुरक्षा बल कार्यालय की इमारत और एक अदालत में आग लगाएं।

सामफेल ने बताया, "मैंने देखा कि चीनी सुरक्षा बलों ने 21 वर्ष की एक तिब्बती महिला ल्हुनढुप सो को गोली मार दी जो कि तिब्बती रेस्टोरेंट और दुकानों के दरवाजे पर खाता (पवित्र स्कार्फ) लटका रही थी। इस तरह का पवित्र खाता इसलिए लटकाया जाता है ताकि दुकान या प्रतिष्ठान की बरकत हो सके। इसके बाद मैंने देखा कि विरोध प्रदर्शन स्थल पर ही दो तिब्बती युवाओं को गोली मार दी गई। शाम को आसपास के गांवों के कई वरिष्ठ भिक्षु और बुजुर्ग तिब्बतियों ने प्रदर्शन रोकने की अपील की क्योंकि उन्हें आशंका थी कि सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई करेंगे और बहुत से लोगों की जानें जाएंगी। इसके बाद आखिरकार विरोध प्रदर्शनकारी अपने घर चले गए। तिब्बत से हाल में आने वाले एक और शरणार्थी जिग्मे ग्यालत्सेन ने भी तिब्बत में जारी बर्बर दमन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "तिब्बत में तिब्बतियो को किसी तरह की आज़ादी नहीं है।"